

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER P.W.D. RAJASTHAN JAIPUR

No. ACE(P)/EE(SS&C)/2021-22/D- 17

Dated: 08/10/2021

Circular

Circular No. CE& AS/ TA-1/EE (D&T)/2016-17/D-126 dated 08.08.2016 issued earlier vide this office regarding use of steel for PWD works is hereby withdrawn.

For all building, road and bridge works executed by PWD, henceforth, as per Ministry and Road Transport & Highway S&R (B) section New Delhi letter no. RW/NH-34066/09/2017-S&R (B) dated 12.02.2021, it has been decided to allow steel produced from ore/billets/pellet/melting of scrap subject to fulfillment of conditions mentioned below. Accordingly, clause 1009.3.1 of Ministry's specification for Road and bridge works has been amended as under:

For plain and reinforced cement concrete (PCC and RCC) or pre-stressed concrete (PSC) works, the reinforcement/ unmentioned steel as the case may be, shall consist of the following grades of reinforcing bars:

Mild steel (MS): Grade-I (conforming to IS 432)

High strength deformed Steel (HSD): Fe415, Fe415D, Fe415S, Fe500, Fe500D, Fe500S, Fe550, Fe550D & Fe600 (conforming to IS 1786)

If any grade of steel given above is not available steel of next higher grade may be used.

For seismic zones III, IV and V, HSD steel bars having minimum elongation of 14.5% shall be used.

For seismic zones III, IV and V, HSD steel bars shall possess following properties:

- a. The actual 0.2% proof strength of steel bars based on tensile test must not exceed their characteristic 0.2% proof strength by more than 20%
- b. The ratio of the actual ultimate strength to the actual 0.2% proof strength/yield strength shall be at least 1.15.

All the manufacturers/ suppliers, as the case may be, shall supply the purchaser or his authorized representative with the certificate stating the process of manufacture and also the test sheet signed by the manufacturer giving the result of each mechanical test applicable for each lot of the material supplied and chemical composition. Sample shall be got tested in the NABL accredited laboratories only, by Executive Engineer concerned. It shall be ensured that all the test results conform to IS 432 (MS) or IS 1786 (HSD).

Only new steel shall be delivered to the site. Every bar shall be inspected before assembling on the work and defective, brittle or burnt bars shall be discarded. Bar with cracked ends shall be discarded.

This shall be applicable for all Building, Road, Bridge and other works executed by Public Works Department of Rajasthan. This circular will be implemented from the date of its issuance.

Sanjiv Mathur
6/10/2021
(Sanjiv Mathur)
CE (Road) & AS PWD
Rajasthan Jaipur

No. ACE(P)/EE(SS&C)/2021-22/D- 17

Dated: 06/10/2021

Copy to following for information and necessary action please:

1. PS to Pr. Secretary, PWD, Govt. of Rajasthan.
2. PS to Secretary, PWD, Govt. of Rajasthan.
3. Chief Engineer cum Addl. Secretary, PWD, Rajasthan
4. Chief Engineer NH/Road/Build/SS/PMGSY/QC PWD Rajasthan
5. MD, RSRDCC Ltd. JhalanaDungari, Jaipur.
6. Financial Advisor, PWD, Rajasthan.
7. Addl. Chief Engineer, PWD, Zone All
8. Superintending Engineer PWD CircleAll
9. Executive Engineer PWD DivisionAll

Sanjiv Mathur
6/10/2021
(Sanjiv Mathur)
CE (Road) & AS PWD
Rajasthan Jaipur

परिपत्र

सविवादात्मक करार जो कि राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर द्वारा संवेदक के साथ किये जाते हैं उनमें वतनेत होने पर निर्णायक मध्यस्थ को भेजे जाने का प्रावधान रखा जाता है। मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 में निर्णित माध्यस्थ (Arbitration) प्रक्रिया अत्यन्त खर्चीली है तथा मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा पारित अर्बिट्रल के प्रावधान भी सीमित है जिससे राज्य के हित विध्वंस रूप से प्रभावित होते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्युत् पाननीय राजस्थान राज्य न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव महोदय को पेशित एक दिनांक 08.08.2019 से सविवादात्मक करारों में माध्यस्थ प्रवर्ग को हटाने का अनुरोध किया गया। महाविद्युत् पाननीय न्यायालय एक्ट 2018 को और भी ध्यान आकर्षित कराते हुए यह राय दी है कि वर्तमान में समस्त वाणिज्यिक भागों को वाणिज्यिक न्यायालय से निर्णित कराया जाना राज्य हित में होगा।

महाविद्युत् पाननीय के द्वारा दिये गये उक्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 एवं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 को प्राप्तियों के संदर्भ में प्रयोज्यता बाधक राज्य सरकार द्वारा संवेदक से किये जाने वाले अनुबंधों में Deletion of Arbitration Clause के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने पर वित्त विभाग की वित्त (जी एण्ड टी) शाखा द्वारा PWF & AR में माध्यस्थ का प्रावधान गृहीत होने का उल्लेख किया है।

तदनुसार निर्दिष्ट किया जाता है कि वृत्ति PWF & AR में मध्यस्थता का प्रावधान नहीं है अतः भविष्य में किये जाने वाले समस्त अनुबंधों में मध्यस्थता का प्रवर्ग नहीं रखा जाये। यदि किसी प्रकरण विशेष में मध्यस्थता प्रवर्ग रखा जाना आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरण में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही मध्यस्थता करार रखा जाना वांछनीय होगा।

राज्य सरकार द्वारा संवेदक से किये जाने वाले अनुबंधों में विवाद होने की स्थिति में वाणिज्यिक न्यायालय/समान सिविल न्यायालय के निर्णय मान्य होंगे, ऐसा प्रावधान अनुबंधों में रखा जाये।

15/12/2022
(राज्यीय सचिव)
मुख्य अभियंता (पर्यावरण अति सचिव)
सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर

G/S / CFO
to be incorporated
in the SBD
16/3/22
ME
16/3/22

प्रतिलिपी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मुख्य अभियंता एवं अति शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- 5 मुख्य अभियंता, पत्राचार/एन-एन/एन/मुजवन्ता निवर्तन/पीएमजीएसआई/विद्युत् सा.नि.वि., राजस्थान।
- 6 प्रबंध निदेशक आरएनएसडीसी लिमिटेड जयपुर।
- 7 निजी सचिव, वित्तीय सहायकार सा.नि.वि., जयपुर।
- 8 समुक्त सिटि पदाधीन, सा.नि.वि., जयपुर।
- 9 अतिरिक्त मुख्य अभियंता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 10 अप्रीक्षण अभियंता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 11 मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/रहायज लेखाधिकारी/खर्च लेखाधिकारी/खर्च लेखाकार (मुजवन्ता)/समस्त रांगा/वृत्त कार्यालय/खण्ड कार्यालय, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 12 अतिरिक्त अभियंता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 13 समुक्त निदेशक (निस्त्व ऐगलिस्ट) सा.नि.वि. को भिजवाकर लेख है कि उक्त परिपत्र को सा.नि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने का अग्र करे।

15/3/2022
(राज्यीय सचिव)



Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.

(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office: Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

Phone: 0141-2711386-90

Fax: 0141-2711178

E-mail: gm@rsrdc.com

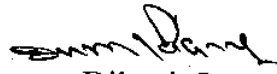
Website: www.rsrdc.com

No. A-5(BPM)Enq./4/I/Gen/2021-22/ 24447-80

Date: 22-03-2022

Copy to:-

1. PS to GM/CPM/CFO, RSRDC Ltd., Jaipur.
2. Dy. General Manager, RSRDC Ltd., (All)
3. Manager, RSRDC Ltd., Jaipur (All)
4. All Project Director, RSRDC Ltd. (All)


(Shyam Bihari Gupta)
Manager (Enquiry)

कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- F-3-15(C)/Environment Rules/Section III/D-2028

दिनांक : 14.12.2021

कार्यालय आदेश

लोक निर्माण वितीय एवं लेखा नियम भाग द्वितीय 334 परिसिष्ट XVI के अनुभाग VII के अन्तर्गत 'ठेकेदारों के रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण प्रधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पर्याप्त ठेकेदार स्वयं के द्वारा और विभागीय क्षेत्र अधिकारियों के द्वारा प्रदायित किये जाने वाले कार्य सम्पादन आंकड़ों के आधार पर पुनर्विलोकन किया जायेगा। कोई ठेकेदार, जिसका कार्य सम्पादन अस्तित्वप्रद पाया जाये, अपना रजिस्ट्रीकरण रद्द करने और नाम रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों की सूची में से करवाने के दायित्वाधीन होगा।'

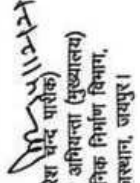
उक्त नियम की पालना में इस कार्यालय में पंजीकृत सिविल/विद्युत/सेनेट्री/भेंटिंग/फर्नीचर के समस्त श्रेणियों (Class) यथा 'AA, A, S-I, P-I, F-I, E-EWSD-I, E-AC-I, E-FF-I, E-LE-I एवं E-ER-I' में पंजीकृत संवेदकों/फर्मों को नोटिस देने के उपरान्त भी पंजीयन का पुनर्विलोकन नहीं करवाया गया है। ऐसे संवेदक/फर्मों को निर्देशित/सूचित किया जाता है कि दो वर्ष (06.12.2019 तक) पूर्व जारी स्थायी पंजीयन आदेशों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक पुनर्विलोकन (Review) आवश्यक रूप से करावा ले। दिनांक 01.01.2022 से उक्त पंजीयन के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं कराये जाने की स्थिति में पंजीयन नियम के अनुच्छेद VII.3.vi के तहत सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को पुनर्विलोकन नहीं कराये जाने तक निविदाओं से भाग लेने से वंचित किया जाता है।


(संजीव माथुर)
14/12/2021

मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

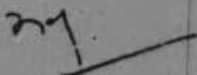
1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सिवाई/जन-स्वास्थ्य अभि. विभाग/मू-जल विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य अभियंता(सिविल) राजराज्य विद्युत प्रसारण निगम लि, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, भिकिस्ता एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. प्रबन्धक निदेशक, अरएस.आर.डी.सी.सी.टि., जयपुर।
7. वितीय सलाहकार, सानि.वि. राजस्थान जयपुर।
8. अति. मुख्य अभियंता, सानि.वि. संगम/विद्युत संगम,.....(समस्त)
9. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियंता(भवन/पथ/सर मार्ग/ई-टैडिंग, मु.अ. कार्यालय, सानि.वि. जयपुर।
10. अधीक्षण अभियंता सानि.वि. वृत्त/विद्युत/रा.रा.उ.मार्ग.....(समस्त)
11. संयुक्त निदेशक, IT, कार्यालय मुख्य अभियंता, सानि.वि. राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
12. जन सम्यक अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, सानि.वि. राजस्थान, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रेषित जारी करने हेतु
13. अधिशासी अभियंता सानि.वि. खण्ड/विद्युत/रा.रा.उ.मार्ग.....(समस्त)
14. बिल्डर एसोसिएशन/संवेदक मूलियन सिविल/विद्युत, जयपुर/समस्त संगम/जिला मुख्यालय को सूचनाएं भेजकर आमह है कि सम्बन्धित संवेदकों को पुनर्विलोकन हेतु आवश्यक दस्तावेज सम्बन्धित पंजीयन प्रधिकारी के कार्यालय में निवृत्त तिथि से पूर्व प्रस्तुत कराये जाने हेतु निर्देशित/सूचित करने का क्रम करें।
15. नैसर्ग


(सुरेश चन्द परोक)
अधिशासी अभियंता (मुख्यालय)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

b/b
b/b/b

	basis for which appropriate proof on Non-Judicial stamp paper will have to be submitted.	
5(b)	Certificate of correctness of bid documents as per annexure 'A'	Certificate of correctness of bid documents shall be submitted on a non judicial stamp paper of Rs 1000/- else it will be assumed that contractor has not submitted the certificate of correctness. If bidder does not upload the certificate of correctness as mentioned above, he shall be considered non responsive in technical bid evaluation.

All concerned are directed to take necessary action accordingly. This bears approval of administrative department vide ID no. Q0133 dated 28.01.2019.


 (M.G. Maheshwari)
 Chief Engineer & Addl. Secretary
 PWD, Rajasthan, Jaipur

No. CE PWD/Sec-III/D:-

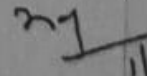
Date:

Copy to the following for information and necessary action :-

1. P.S. to Addl. Chief Secretary, PWD Rajasthan, Jaipur.
2. P.S. to Secretary, PWD Rajasthan, Jaipur.
3. Chief Engineer (NH/PMGSY/SS/Bldg.) PWD, Rajasthan, Jaipur.
4. MD, RSRDC.

No. 52

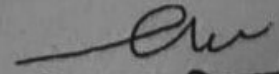
Date 25/04/19

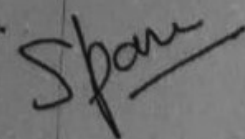

 (M.G. Maheshwari)

Copy to SE PWD circle BTP/ Dholpur/Korauli for info & m/s. The circular may also be circulated among ECs under their control for strict & sincere compliance

Chief Engineer & Addl. Secretary
 PWD, Rajasthan, Jaipur

(Handwritten note: The circular may also be circulated among ECs under their control for strict & sincere compliance)


 अति मुख्य अभियन्ता
 सा० नि० वि० जोन, भरतपुर





Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office: Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

No. B-2(1) SBD/ 31390-453

Date: 27-12-17

CIRCULAR

The criteria for calculation of eligibility in experience certificate of RSRDC Contractors is hereby modified as under for the tenders bids to be received under general agreement as well as Standard Bid Documents, if cement/steel or both were supplied free of cost by RSRDC for the works executed by the Contractor as follows :-

1. The eligibility amount will be increased by 10% in the experience certificate, if only cement is supplied free of cost.
2. The eligibility amount will be increased by 25% in the experience certificate, if only steel is supplied free of cost.
3. The eligibility amount will be increased by 35% in the experience certificate, if cement & steel both are supplied free of cost.

The enhancement of experience will only be considered provided the experience certificate clearly mentions that materials (cement/steel or both) are supplied by the RSRDC free of cost to the Contractor for execution of work.

This bears approval of the Competent Authority.

(G. Mukhija)
General Manager

1. PS to MD/GM/CFO RSRDC Ltd., Jaipur.
2. Chief Project Manager, RSRDC Ltd. (All)
3. Dy. G.M., RSRDC Ltd. (All)
4. Sr. A.O. (Tender), RSRDC Ltd., Jaipur.
5. Manager, RSRDC Ltd., (All)
6. Project Director, RSRDC Ltd. (All)

SR RKS
note
28-01-2021

General Manager

copy to Project Director (Ad) for compliance of circular
Shilwara

LPBX - 2711386-90

Email: gm@rsrdc.com

Fax: 0141-271178

Website: RSRDC.Com

28/1/21
(Anish Dhatla)
Manager (Admn.)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 06.11.2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the Works Contract shall be reduced and charged as under:-

S.No.	Amount or value of the works contract	Stamp duty
1.	upto Rupees Fifty Lakhs	Rupees One Thousand
2.	more than Fifty Lakhs	0.15% of the amount or value of the works contract subject to maximum of Rupees Twenty Five Lakhs

[No.F.2(31)FD/Tax/2019-253]

By order of the Governor,


(Nishant Jain)

Joint Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) of extra ordinary gazette Kindly send 10 copies of this notification to this department and 20 copies along with bill to Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
2. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance), Rajasthan, Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
5. PS to Additional Chief Secretary, Public Works Department.
6. PS to Principal Secretary, Finance Department.
7. PS to Principal Secretary, Law Department.
8. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
9. Director, Public Relation Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Technical Director, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
11. Guard file.


Joint Secretary to the Government



Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doonguri, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

No. B-2(1)SBD / 6994 - 7044

Date: 06-06-2023

OFFICE ORDER

Amendment is hereby made in clause no. 4.4 and 4.5 of Standard Bid Document (SBD) of RSRDC Ltd. with immediate effect as under:-

S. No.	Page No.	Reference Clause	Existing Clause	Revised Clause
1	5	4.4.8	The lead partner shall meet not less than 50 percent of all the qualifying criteria given in Clause 4.5.1.1 & 4.5.2.3 below. The Joint Venture must collectively satisfy the criteria of clause 4.5.1.1 & 4.5.2.3 below. The experience of the other joint venture shall be considered if it is not less than 30 per cent of the qualifying criteria given in 4.5.1.1 & 4.5.2.3 below. However, in case one of the joint venture partners is proposed to be included primarily to provide financial strength to the joint venture, such joint venture partner shall have to commit to provide liquidity support to the project to the extent of 10 percent of the value of the contract.	The lead partner shall meet not less than 50 percent of all the qualifying criteria given in Para 4.5.1.1 & 4.5.1.2 below. The joint venture must collectively satisfy the criteria of Para 4.5.1.1 & 4.5.1.2 below. The experience of the other joint venture partners shall be considered if it is more than 30 percent of the qualifying criteria given in Para 4.5.1.1 & 4.5.1.2.
2	5	4.4.9	The joint venture must satisfy collectively the criteria of clause 4.5.1.2, 4.5.2.1 and 4.5.2.2 below for which purpose the relevant figures for clause 4.5.2.1 and 4.5.2.2 and numbers for clause 4.5.1.2, for each of the partners shall be added together to arrive at the joint venture's total capacity.	The joint venture must satisfy collectively the criteria of clause 4.5.2.1 & 4.5.2.2 below for which purpose the relevant figures for clause 4.5.2.1 and 4.5.2.2, for each of the partners shall be added together to arrive at the joint venture's total capacity.

Contd.Page 2

2



Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

--2--

3	5	4.4.3	One of the partners shall be nominated as being in-charge or lead partner, and this authorization shall be evidenced by submitting a power of attorney signed by legally authorized signatories of all the partners.	One of the partners shall be nominated as being in-charge or lead partner i.e. having major share in Joint Venture and other partner shall have at least 30% share in Joint Venture. This authorization shall be evidenced by submitting a power of attorney signed by legally authorized signatories of all the partners.
4	6	4.5.1.2	Satisfactorily completed (Phase/Part completion of the scope of work in a contract shall not be considered) three works, value of each shall be 40%, or two works value of each shall be 50%, or one work value of which shall be 80% of estimated cost, at least one similar work of value not less than the amount indicated in Annexure-I. the eligibility amount may be suitably increased to consider the effect of department supply of steel and cement, if any in compliance to RSRDC circular B-2(1)SBD/31390-453 dt. 27.12.2017	Satisfactorily completed (Phase/Part completion of the scope of work in a contract shall not be considered) three works, value of each shall be 40%, or two works value of each shall be 50%, or one work value of which shall be 80% of estimated cost (In case of Joint Venture Lead Partner shall fulfill the requirement). at least one similar work of value not less than the amount indicated in Annexure-I. (a) As a prime contractor, or (b) As a nominated sub contractor (nominated or selected or approved by a Govt. organization) where the sub contract involved execution of all main items of works described in bid document.; provided further all other qualification criteria are satisfied. The eligibility amount may be suitably increased to consider the effect of department supply of steel and cement, if any in compliance to RSRDC circular B-2(1)SBD/31390-453 dt. 27.12.2017

Contd..... Page-3



Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)


(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

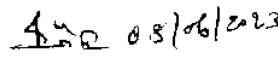
-----3-----

This bears approval in 119th Board Meeting of RSRDC held on 26th day of May, 2023. Minutes of the Meeting issued on 31st day of May 2023 and amendment approved vide item no. 119.04.


(Sanjay Saxena)
General Manager

Copy Forwarded to the following:-

1. PS to Chairman, RSRDC Ltd., Jaipur.
2. PS to MD/ CFO, RSRDC Ltd., Jaipur.
3. GM/CPM, RSRDC Ltd., Jaipur.
4. Dy. G.M., RSRDC Ltd., All
5. Sr. A.O. (Payment), RSRDC Ltd., Jaipur.
6. Manager, RSRDC Ltd., All.
7. Project Director, RSRDC Ltd., All.
8. GE.


08/06/2023
Manager (Admn.)



Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.

(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004


No. B-2(1)SBD/ 15043-86

Date: 22-11-2021

OFFICE ORDER

The Joint Venture (JV) shall be allowed only for tenders of bid amount costing Rs. 25.00 Crore or more in Building works & Rs. 50.00 Crore or more in Road & Bridge works. Therefore respective Joint Venture clauses/Provisions shall be applicable accordingly.

This order shall be applicable with immediate effect.


(Sandeep Mathur)
Managing Director

Copy Forwarded to the following:-

1. PS to Chairman, RSRDC Ltd., Jaipur.
2. PS to MD/Chief Architect/CFO, RSRDC Ltd., Jaipur.
3. GM/CPM, RSRDC Ltd., Jaipur.
4. Dy. G.M., RSRDC Ltd., (All).
5. Sr. A.O. (Payment)/ (Pension), RSRDC Ltd., Jaipur.
6. Manager, RSRDC Ltd., (All).
7. Project Director, RSRDC Ltd., (All).
8. Sr. L.O., RSRDC Ltd., Jaipur.
9. Notice Board.
10. PF/ GF.


Managing Director



Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

क्रमांक : बी-9(6)SBD/98 / 18207 - 40

दिनांक: 05-01-2021

कार्यालय आदेश

निगम मुख्यालय के आदेश क्रमांक बी-10(5)/26909-61 दिनांक 26.12.2012 को अधिक्रमण (supersession) करते हुए राज्य योजनाओं में लागत राशि रू0 10.00 लाख से अधिक के कार्यों की दोष निवारण की अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का प्रकार	दोष निवारण अवधि
1.	सड़क नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य	5 वर्ष
2.	नवीन सड़क/भवन/पुल/सीडी कार्य	5 वर्ष
3.	सड़क चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण एवं उन्नयन कार्य	5 वर्ष

यह आदेश जारी करने की दिनांक से प्रभावी है तथा प्रगतिरत एवं आगामी समस्त निविदाओं में शामिल किया जाना है।

Sd.
(एस.सी. अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
3. महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड, (समस्त)।
5. प्रबन्धक, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड, (समस्त)।
6. परियोजना निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड, (समस्त)।
7. व्यक्तिगत पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

Sd.
5/1/2021
प्रबन्ध निदेशक



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 30, शुक्रवार, शके 1943-अक्टूबर 22, 2021
Asvina 30, Friday, Saka 1943- October 22, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, October 22, 2021

G.S.R.364 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Fourth Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of new rule 75A.- After the existing rule 75 and before the existing rule 76 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the following new rule 75A shall be inserted, namely:-

"75A. Additional Performance Security.- (1) In addition to Performance Security as specified in rule 75, an Additional Performance Security shall also be taken from the successful bidder in case of unbalanced bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of Unbalanced Bid Amount. The Additional Performance Security shall be deposited in lump sum by the successful bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited through e-Grass, Demand Draft, Banker's Cheque, Government Securities or Bank Guarantee.

Explanation : For the purpose of this rule,-

- (i) Unbalanced Bid means any bid below more than fifteen percent of Estimated Bid Value.
- (ii) Estimated Bid Value means value of subject matter of procurement mention in bidding documents by the Procuring Entity.
- (iii) Unbalanced Bid Amount means positive difference of eighty five percent of Estimated Bid Value minus Bid Amount Quoted by the bidder.

(2) The Additional Performance Security shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of the entire work. The Additional Performance Security shall be forfeited by the Procuring Entity when work is not completed within stipulated period by the contractor. Provision for 'Unbalanced Bid' and 'Additional Performance Security' shall be mentioned in the Bidding Documents by the Procuring Entity."

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]
By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

B-2 (1) 12619 - 53

Date - 22-10-2021

Forwarded to PS TO GM, CPM, Dy GM - All,
Manager - All, Project Director - All for
compliance of notification.

sh rawan
22/10/21
(S. S. Shekhawat)
Jr. Asstt. (Admn. Cell)
RSRDC Ltd., Jaipur

~~Manager (Adm.)~~

m/mt 22/10/21
(Anish Bhatia)
Manager (Admn.)
RSRDC Ltd., Jaipur